RNI NO - UPHIN/2022/86937

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 60 | जौनपुर सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

वंचित वर्ग के हक में लोहिया का संघर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सदैव पथ प्रदर्शक रहेगा : योगी आदित्यनाथ

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में गैर–कांग्रेसवाद की अलख जगाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर रविवार को उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वंचित वर्ग के हक में डॉ लोहिया का संघर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सदैव पथ प्रदर्शक रहेगा। योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, '''सप्त क्रांति' के सूत्रधार, प्रखर समाजवादी चिंतक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉ. राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि!'' योगी ने कहा, ''गरीब, किसान, श्रमिक और वंचित वर्ग के उत्थान एवं सामाजिक न्याय को

लेकर आपका (लोहिया का) संघर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सदैव पथ प्रदर्शक रहेगा।'' उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 'एक्स' पर अपने पोस्ट में कहा, ''महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि!'' मौर्य ने कहा, ''डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने सशक्त लोकतंत्र की स्थापना हेतु अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर सामाजिक न्याय एवं समानता की एक अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत की।'' उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 'एक्स' पर कहा, ''भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर राजनीतिक चिंतक एवं समाजवादी राजनेता डॉ० राम मनोहर लोहिया जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन।'' डॉ लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को हुआ था और उनका निधन 12 अक्टूबर 1967 में हुआ था। लोहिया एक स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी विचारों को मानने वाले थे। उन्होंने वंचित समुदायों के राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए मजबूती से काम किया और कांग्रेस के तत्कालीन आधिपत्य के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम भी किया।

भारत मजबूत और एकजुट रहे, ये संविधान ने सुनिश्चित किया

मुंबई। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने रविवार को कहा कि हमारे संविधान ने सुनिश्चित किया है कि देश मजबूत और एकजुट रहे, जबकि पड़ोसी देश अशांति और उथल–पुथल का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मंदनगढ़ तालुका में एक न्यायालय भवन का उद्घाटन करने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह भवन ऐसे क्षेत्र में बना है जहां संविधान के मुख्य निर्माता और महान समाज सुधारक बाबासाहेब आंबेडकर का पैतृक गांव अंबावडे भी स्थित है।आया उसने मजबूती और एकजुटता के साथ उसका सामना किया और इसका श्रेय संविधान को दिया जाना चाहिए । यहां इलाहाबाद हाई कोर्ट में 680 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित अधिवक्ता चौंबर भवन और मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन करने के बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गवई ने कहा कि न्यायपालिका का मौलिक कर्तव्य देश

के उस आखिरी नागरिक तक पहुंचना है जिसे न्याय की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि विधायिका और कार्यपालिका का भी यही कर्तव्य है। सीजेआई ने कहा, जब भी संकट आया, भारत एकजुट और मजबूत रहा। इसका श्रेय संविधान को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, भारतीय संविधान लागू होने की 75 वर्ष की ।

संक्षिप्त खबरें

सांसद पर हमला लोकतंत्र के खिलाफ सीधी कार्रवाई

तिरुवनंतपुरम, (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल के वडाकरा से कांग्रेस सांसद शफी परमबिल पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है, उन्होंने कांग्रेस सांसद पर हमले को अस्वीकार्य बताया और कहा कि सांसद पर हमला लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। थरूर ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्षी सांसदों को बिना किसी डर और बिना किसी कानूनी कार्यवाही की चिंता के विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में शशि थरूर ने लिखा कि श्सांसद शफी परमबिल पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस का हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। एक लोकतंत्र में सांसदों को खासकर जो विपक्ष में हैं, बिना किसी डर के विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों और कानूनी सुरक्षा का उल्लंघन करती हैं। इस मामले में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जब सांसदों को विरोध प्रदर्शन करने के लिए निशाना बनाया जाता है यह लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर करता है। पुलिस की एक सांसद के खिलाफ निर्ममता न सिर्फ गलत है बल्कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। थरूर ने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने रखेगी। उन्होंने कहा कि श्भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, जहां सांसद कानून से ऊपर नहीं हैं, लेकिन उन्हें कानून में कुछ छूट मिली हुई है, जिससे वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को बिना किसी डर के पूरा कर सकें। कांग्रेस इस मामले को संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने उठाएगी।

देश के लिए गए थे, पीएम के लिए नहीं – ओवैसी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। ऑल इंडिया मजलिस– ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत द्वारा किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' की खुलकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार–बार गलतियां करता है, इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा देश के पक्ष में खड़ी है और उन्होंने विदेश में जाकर देश की बात रखी, न कि पीएम के लिए। ओवैसी उन प्रति निधिमंडलों में शामिल थे जिन्हें भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद साझेदार देशों में भेजा था ताकि दुनिया को भारत की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति के बारे में बताया जा सके। ओवैसी ने कहा कि हम हमेशा देश का पक्ष रखने के लिए तैयार हैं। हम प्रधानमंत्री के लिए नहीं, देश के लिए गए थे। जब पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, तो यह स्वाभाविक था कि देश की ओर से एकजुट होकर जवाब दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार की रणनीति अब अलग है। 26/11 के समय जो रणनीति थी, वह अलग थी।

तारे ने मुझे शिंदे के बारे में चेतावनी दी थी, उनकी बात माननी चाहिए थी – उद्धव ठाकरे

नई दिल्ली, (एजेंसी)। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि पार्टी के दिवंगत नेता अनंत तारे ने 2014 में ही उन्हें एकनाथ शिंदे के बारे में चेतावनी दी थी और उन्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए था। ठाणे के तीन बार महापौर रहे तारे पर एक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर ठाकरे ने कहा कि शिवसेना ने 2014 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जो

उस समय उसकी सहयोगी थी, उसे ''नष्ट'' करने की योजना बना रही थी। ठाकरे ने महाराष्ट्र के वर्तमान उपमुख्यमंत्री शिंदे का नाम लिए बिना कहा कि तारे ने उनसे कहा था कि यह आदमी एक दिन उन्हें धोखा देगा। शिंदे ने ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया था और जून 2022 में उनके नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को गिरा दिया था। इसके बाद शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने भाजपा से हाथ मिला लिया और वह मुख्यमंत्री बन गए। इस बीच, ठाकरे ने यह भी कहा कि ठाणे कभी शिवसैनिकों का शहर था, लेकिन अब यह ठेकेदारों का शहर बन गया है। ठाणे शहर शिंदे का गढ़ माना जाता है।

राजमाता सिंधिया के समाज सेवा के प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा- प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पीएम नरेन्द्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की संस्थापक सदस्य राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर रविवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी। मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''समाज सेवा के उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने जनसंघ और भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।'' पीएम ने कहा, ''विजयाराजे सिंधिया जी हमारी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति गहरी आस्था रखती थीं और उनकी रक्षा करने के साथ–साथ उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए हमेशा काम करती थीं।'' ग्वालियर की राजमाता के नाम से जानी जाने वाली सिंधिया का जन्म 12 अक्टूबर 1919 को

मध्य प्रदेश के सागर में हुआ था। लोकसभा की सात बार सदस्य रहीं सिंधिया ने 25 जनवरी 2001 को अंतिम सांस ली थी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत का सपना आत्मनिर्भर भारत के जरिये साकार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजमाता ने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई और उनके आदर्श आज भी राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणास्रोत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की जयंती पर कोटि–कोटि नमन। समाज सेवा के उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने जनसंघ और भाजपा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विजयाराजे सिंधिया जी हमारी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति गहरी आस्था रखती थीं और उन्हें संरक्षित व लोकप्रिय बनाने के लिए सदैव कार्यरत रहीं।" प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 1 मिनट 19 सेकंड का एक वीडियो संदेश भी साझा किया। इसमें उन्होंने कहा, "पिछली शताब्दी में भारत को दिशा देने वाले कुछ चुनिंदा व्यक्तित्वों में राजमाता विजयाराजे सिंधिया शामिल थीं। वह केवल वात्सल्य मूर्ति ही नहीं, बल्कि एक निर्णायक नेता और कुशल प्रशासक थीं।

सरकार महिला की विफलता छिपाना चाहती सरकार : अखिलेश यादव

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने महिला अपराधों पर एक बार फिर सरकार को घेरा है। कहा कि भाजपा द्वारा प्रस्तुत किए गए एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, महिलाएं बड़े पैमाने पर असुरक्षित हैं। भाजपा अपनी विफलता छिपाना चाहती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पीड़न और अन्याय लगातार हो रहा है। हर विभाग में भ्रष्टाचार है। जिन विभागों को उत्तर प्रदेश के लोगों को सुविधाएं और सहायता प्रदान करनी चाहिए, उनके नौ साल के शासन के दौरान हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने कहा कि उत्तर

प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र दूसरे व राजस्थान तीसरे स्थान पर है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया के प्लेटफार्म एक्स पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि सच से आंखे नहीं मूंदनी चाहिए। कभी एनसीआरबी की रिपोर्ट भी पढ़नी चाहिए। अपना स्तुति गान स्वयं बघारना शोभा नहीं देता है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के विरुद्ध अपराध के प्रदेश में कुल 66,381 मामले दर्ज हुए और अपराध दर 58.6 प्रतिशत रही। जबकि राष्ट्रीय अपराध दर 66.2 प्रतिशत रही। प्रति एक लाख जनसंख्या के सापेक्ष अपराधों की संख्या को अपराध दर (क्राइम रेट) के रूप में परिभाषित किया गया है। महिला सम्मान भंग (शील भंग) से जुड़े मामलों में उत्तर प्रदेश का 19वां स्थान रहा। देश में ऐसे मामलों की कुल संख्या 83,891 रही और अपराध दर 12.4 प्रतिशत रही। जबकि उत्तर प्रदेश 9,453 मामले दर्ज हुए और अपराध दर 8. 3 प्रतिशत रही। बच्चों के विरुद्ध अपराध में भी अपराध दर राष्ट्रीय दर से कम रही और उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान रहा।

कांग्रेस नेता ने की राहुल के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने शुक्रवार को राहुल गांधी और 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो के बीच तुलना करते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता भी देश में संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर एक पोस्ट में राजपूत ने कहा कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला के विपक्षी नेता को दिया गया था, और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद गांधी भी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के हकदार हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट राजपूत ने कहा कि इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला के विपक्ष के नेता को संविधान की रक्षा के लिए दिया गया है। भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत के पोस्ट पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग पर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। शहजाद पूनावाला एक्स पर एक किए पोस्ट में राहुल गांधी की तुलना मारिया कोरिना से करने को विचित्र बताया। भाजपा के

राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस राहुल बाबा के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर रही है, यह विचित्र है। उन्हें यह पुरस्कार 1 पाखंड, झूठ, 99 बार चुनाव हारने और 1975 और 1984 में लोकतंत्र और संविधान की हत्या के लिए मिलना चाहिए। अगर कोई नोबेल पुरस्कार इन चीजों के लिए हो तो उन्हें मिल ही जाएगा। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने शुक्रवार को घोषणा की कि वेनेजुएला में विपक्ष का नेतृत्व करने वाली 58 वर्षीय मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा। एक बयान में कहा गया कि मचाडो को वेनेजुएला में शांति को बढ़ावा देने और वहां के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार दिलाने के उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। समिति ने कहा कि मचाडो वेनेजुएला में विपक्ष को एकजुट करने में एक प्रमुख नेता रही हैं, जो वर्तमान में मानवीय और आर्थिक संकट से गुजर रहा है।

इंदिरा गांधी ने अपनी जान देकर चुकाई ऑपरेशन ब्लू स्टार की कीमत : चिदंबरम

नई दिल्ली, (एजेंसी)। साल 1984 में पंजाब के अमृतसर में स्थित सिखों के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर के अंदर उग्रवादियों पर काबू पाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री

इंदिरा गांधी ने सैन्य कार्रवाई की इजाजत दी थी. इस ऑपरेशन के कारण इनकी राजनीतिक स्थिती काफी प्रभावित हुई थी और आखिरकार उनकी हत्या कर दी गई थी. इसे लेकर कांग्रेस पर सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगता आया है. । अब कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि स्वर्ण मंदिर को वापस पाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई. चिदंबरम हिमाचल प्रदेश के कसौली में खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव में बोल रहे थे. वे पत्रकार हरिंदर बावेजा की किताब ष्दे विल शूट यू, मैडम पर चर्चा कर रहे थे। जून 1984 में भारतीय सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था. इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है. इस ऑपरेशन के बाद इंदिरा गांधी की उनके ही सिख सुरक्षाकर्मियों ने हत्या कर दी थी। चदंबरम ने कहा, श्यहां किसी भी फौजी अफसर का अनादर नहीं कर रहा, लेकिन स्वर्ण मंदिर को वापस पाने का यह गलत तरीका था. कुछ साल बाद हमने सही तरीका दिखाया – सेना को बाहर रखकर. ब्लू स्टार गलत तरीका था और मैं मानता हूं कि श्रीमती गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई. चिदंबरम ने यह भी कहा कि यह फैसला अकेले इंदिरा गांधी का नहीं था. उन्होंने बताया कि यह सेना, पुलिस, गुप्तचर विभाग और सिविल सेवा का मिलाजुला फैसला था. उन्होंने कहा, इसका दोष केवल श्रीमती गांधी पर नहीं मढ़ा जा सकता। क्या आप ऐसा करेंगे? यह सवाल उन्होंने लेखिका हरिंदर बावेजा से पूछा।

गोयल ने कनाडा के समकक्ष के साथ की वर्चुअल बैठक

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत और कनाडा के बीच हाल के दिनों रिश्ते तनावपूर्ण रहे। हालांकि मार्क कार्नी के कनाडा के पीएम बनने के बाद से दोनों देशों के रिश्ते में कुछ सकारात्मक पहल भी देखने को मिले। ऐसे में अब भारत और कनाडा के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए साथ ही आर्थिक संबंधों में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के बीच अहम चर्चा हुई। इस दौरानों दोनों नेताओं ने भारत और कनाडा के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। इसके अलावा नेताओं ने दोनों देशों के बीच भरोसे, सम्मान और संतुलन पर आधारित साझेदारी को आगे बढ़ाने की बात भी कही। कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ हुई इस बैठक के बारे में पीयूष

गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि हमने ऐसे अवसरों पर चर्चा की जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं का लाभ उठाते हुए व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने जोर देकर कहा कि भारत–कनाडा के व्यापारिक रिश्ते आपसी सम्मान, विश्वास और संतुलन पर आधारित होने चाहिए। इस बैठक को लेकर कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने भी कहा कि वे भारत के साथ आर्थिक जुड़ाव को गहरा करने और क्लीन टेक्नोलॉजी, एआई, कृषि, और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में नए व्यापारिक अवसरों पर काम कर रहे हैं। बता दें कि 2023 में कनाडा ने भारत के साथ चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) की बातचीत को रोक दिया था। इसके पीछे कारण था कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा एक सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत पर कथित संलिप्तता का आरोप लगाना। भारत ने इन आरोपों को बिल्कुल बेबुनियाद बताया था। हालांकि, दोनों देशों ने मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता (ईपीटीए) को लेकर बातचीत दोबारा शुरू की थी। अब तक इस पर छह से ज्यादा दौर की बातचीत हो चुकी है। वहीं बात अगर दोनों देशों के बीच हुए व्यापार के आंकड़े की करें तो भारत का कनाडा को निर्यात 2023–24 में 3.84 अरब डॉलर से बढ़कर 2024–25 में 4.22 अरब डॉलर हो गया, जिसमें 9.8: की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं कनाडा से आयात 4. 55 अरब डॉलर से घटकर 2024–25 में 4.44 अरब डॉलर रह गया।

संपादकीय

टिकाऊ शांति का रास्ता ?

फिलहाल, गजा के बाशिंदों को बड़ी राहत मिली है। मगर अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने दो–राज्य सिद्धांत के तहत स्वतंत्र फिलस्तीन की स्थापना करवाने की चुनौती है, जिसके बिना कोई समझौता स्थायी शांति नहीं ला पाएगा। इजराइल और हमास के बीच शांति समझौते के पहले चरण पर सहमति बनने के साथ गजा में लड़ाई रुकने की संभावना मजबूत हुई है। यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की 20 सूत्री शांति योजना के तहत हुआ। इसके मुताबिक इजराइल हमले तुरंत रोकने और गजा से अपनी फौज की आंशिक वापसी पर राजी हुआ है। बदले में हमास 20 जिंदा इजराइली बंधकों और 28 बंधकों के शव लौटाएगा। इजराइल उम्र कैद काट रहे 250 से अधिक फिलस्तीनियों को रिहा करेगा। इसके अलावा वह 1,700 उन फिलस्तीनियों को रिहा करेगा, जिन्हें सात अक्टूबर 2023 के बाद से उसने हिरासत में ले रखा है। इसके बाद क्या होगा, इस पर शांति समझौते के दूसरे चरण में बातचीत होगी। इस दौरान गजा में राजनीति प्रशासन एवं सुरक्षा का नया ढांचा बनाने के सवाल पर वार्ता होगी। इस पर रजामंदी होना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। हमास ने कहा है कि श्राष्ट्रीय स्वतंत्रता और आत्म–निर्णय का अधिकारस्य हासिल करने के संकल्प पर वह अडिग है। गजा का प्रशासन फिलस्तीनियों के हाथ में रहे, इसे वह सुनिश्चित करेगा। क्या इजराइल इसके लिए राजी होगा? या इस सवाल पर बातचीत टूट जाएगी और फिर से गजा में मानव संहार का नजारा देखने को मिलेगा? ये इस समय सबसे प्रासंगिक प्रश्न हैं। हमास ने टिकाऊ शांति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ष्समझौते के गारंटरष ट्रंप तथा उन अरब– इस्लामी देशों पर डाली है, जिनके हस्तक्षेप से समझौते का पहला चरण संपन्न हो सका। आम समझ है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समझौते के लिए तैयार नहीं थे, मगर ट्रंप का दबाव निर्णायक साबित हुआ। ट्रंप ऐसे ही रुख पर कायम रहे, तो शायद बात आगे बढ़ सकेगी। फिलहाल, गजा के बाशिंदों को बड़ी राहत मिली है। इजराइली हमलों में लगभग 67,000 लोग मारे गए। गजा का बुनियादी ढांचा लगभग तबाह हो गया है। अब उसके पुनर्निर्माण और वहां बचे लोगों को नई जिंदगी देने की चुनौती अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने है। मगर उसके सामने उससे भी बड़ी चुनौती दो–राज्य सिद्धांत के तहत स्वतंत्र फिलस्तीन की स्थापना करवाने की है, जिसके बिना कोई समझौता स्थायी शांति नहीं ला पाएगा।

राहुल के ननिहाल में पीएम मोदी की दोस्त का बवाल

अभिनय

राहुल गांधी के नानी के घर और सोनिया गांधी के मायके में इन दिनों भयंकर बवाल मचा है। इटली की राजनीति में इन दिनों बड़ा तूफान आया है। तूफान की चपेट में बुर्का, मस्जिदें और धार्मिक स्वतंत्रता हैं। इसका सीधा संबंध भारत की राजनीति से भी जुड़ता है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को पीएम मोदी का खास दोस्त बताया जाता है। उन्होंने अब ऐसा कदम उठाया है। जिससे यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया की सियासत गर्मा गई है। मेलोनी सरकार बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। यानी इटली में बुर्का बैन होगा। वैसे तो दुनिया में 24 देश ऐसे हैं जिन्होंने बुर्का और हिजाब पर बैन लगाया हुआ है। कई देश तो ऐसे हैं जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उन्होंने भी धर्म निरपेक्षता के नाम पर अपने यहां बैन लगाया है। ऐसा ही एक नाम अब इटली का सामने आया है। इटली में जिस तरह से पिछले दिनों फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगे और सड़कों को जाम किया गया। लाखों लोग सड़कों पर उतरे। उन तस्वीरों ने और ज्यादा इटली के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर देश के भविष्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए। जिस इटली को राहुल गांधी का ननिहाल कहा जाता है वहां अब मोदी की दोस्त ने ऐसा सियासी पासा

फेंका है जो सीधे तौर पर भारत के कट्टरपंथियों की भी हवा निकाल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या यूरोप में अब नए सांस्कृति टकराव की शुरुआत हो चुकी है। पहले जो फ्रांस में देखने को मिला वो अब इटली में देखने को मिल रहा है। क्या मेलोनी का ये कदम भारत की राजनीति में भी गूंजेगा? इटली की सत्ता संभालने वाली जॉर्जिया मेलोनी ने संसद में एक बिल पेश किया है। इस बिल में कहा गया है कि देशभर में बुर्के पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। स्कूल, दुकानें हो या ऑफिस हर पबल्कि प्लेस पर अब चेहरा ढकना जुल्म माना जाएगा। मस्जिदों की फंडिंग पर निगरानी होगी। इसके अलावा जबरन धार्मिक विवाह पर रोक होगी। नकाब पहनने पर भारी जुर्माने का प्रावधान इस बिल में शामिल है। इटली की सत्तारूढ़ पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली की तरफ से कहा गया हैकि देशभर में सार्वजनिक स्थानों पर नकाब और बुर्का से चेहरा और शरीर ढकने पर प्रतिबंध लगेगा। हालांकि ये प्रतिबंध अभी भी देश के कुछ हिस्सों में है। लेकिन इस विधेयक के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। पार्टी ने इस्लामी अलगाववाद के खिलाफ विरोध विधेयक बताया है। विधेयक के योजनाकारों में सांसद एंड्रिया डेल मास्ट्रो ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता पवित्र है। लेकिन इसा खुलेआम प्रयोग हमारे संविधान और इटली राज्य के सिद्धांतों का पूरा सम्मान करते हुए किया जाना चाहिए। ओपन बॉर्डर पॉलिसी को इटली के अलावा और भी कई यूरोपीय देशों ने अपनाई थी। जिसकी वजह से पिछले 20–25 सालों में वहां बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी गए हैं। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। पालिटिको की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिबंध के तहत दुकानों, स्कूलों और दफ्तरों समेत सभी सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने पर रोक होगी। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर 300 से 3 हजार यूरो यानी लगभग 3 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने देश में बढ़ते इस्लामीकरण का आरोप लगाया। इस्लामी प्रतीकों के सार्वजनिक प्रदर्शन को सांस्कृतिक अलगाववाद के रूप में बताया है। बुर्का बैन के साथ–साथ इसी बिल में स्जिदों की फंडिंग को भी नियंत्रित करने प्रावधान है। ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी इमीग्रेशन प्रमुख सारा कैलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बिल के बारे में बताया। उन्होंने कहा यह एक ऐसा विधेयक है जो मुख्य तौर पर मस्जिदों की फंडिंग को अनियमित करने और पूरे चेहरे को ढकने वाले नकाब के उपयोग को रोकने और उस पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित होगा। यह जबरन शादी के विरुद्ध कानून पर भी जोर देता है। केलानी ने आगे कहा कि हम इटली में अपने कानूनों को लागू करते हैं जो विशिष्ट मूल्यों पर आधारित है। डेल मास्टरों ने कहा कि इटली ने फ्रांस से प्रेरणा ली है जो 2011 में बुर्के पर बैन लगाने वाला पहला यूरोपीय देश था। इसके बाद बेल्जियम, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और यूरोप के कई देशों ने इस पहल की शुरुआत की। इस्लाम से संबंधित महिलाओं के कपड़ों पर पूर्ण का आंशिक प्रतिबंध लगा दिया। इटली की कुल आबादी लगभग 60 मिलियन है। जिसमें से मुस्लिम आबादी 17 लाख से लेकर 27 लाख बताई जा रही है। जो कुल आबादी का लगभग 5 फीसदी होने का अनुमान है। आईएसएमयू 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी निवाशियों में से जितने भी प्रवासी इटली आए हैं उनमें 30 फीसदी मुसलमान हैं, जो मोरक्को, अल्बानिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हुए हैं। पीयू रिसर्च के अनुसार 2.3 से 2.7 मिलियन तक ये आंकड़घ हो सकता है। ये अपने आप में डराने वाला आंकड़ा है। यूरोप के कुछ देशों में पिछले दो तीन सालों से विशेषकर फ्रांस में जिस तरह से तांडव देखने को मिला। 2023 में हफ्ते भर तक फ्रांस जलता रहा था, जिसका एक बड़ा कारण ओपन बॉर्डर पॉलिसी को बताया गया था। नया बिल सिर्फ चेहरा ढकने वाले कपड़ों तक सीमित नहीं है। इसमें उन धार्मिक संगठनों पर भी निगरानी की बात कही गई है जो इटली की सरकार के साथ औपचारिक समझौते में नहीं है। फिलहाल इस्लाम को इटली में वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। जबकि 13 अन्य धर्मों के पास यह अधिकार है। इसलिए यह बिल मुस्लिम संगठनों को अपने फंडिंग सोर्सेज सार्वजनिक करने और संदिग्ध फाइनेंसरों से दूरी रखने को अनिवार्य करता है। इसके साथ यह कानून वर्जिनिटी टेस्ट कराने वालों पर भी सजा का प्रावधान लाता है और जबरन धार्मिक विवाहों में ६ार्मिक दबाव को अपराध की श्रेणी में लाता है। फिलहाल इटली की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के पास संसद में पूर्ण बहुमत है। इसलिए इस बिल के पारित होने की संभावना बेहद मजबूत है। इटली से इतर भारत में हिजाब और बुर्के का मुद्दा लगातार चर्चा में रहता है। कॉलेजों में हिजाब के मुद्दे को लेकर ये अदालत के दरवाजे तक भी पहुंच चुका है। हालांकि भारत में बुर्का बैन होना फिलहाल संभव नहीं लगता क्योंकि यह बेहद संवेदनशील और विवादास्पद विषय है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर राष्ट्र है जहां संविधान द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता की पूरी गारंटी दी जाती है। जिसका सीधा फायदा कट्टरपंथी उठाते भी हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच बीजेपी ने अचानक बुर्का बैन की मांग उठाकर सियासी तापमान बढ़ाया था। इससे विपक्षी पार्टी खासकर आरजेडी और कांग्रेस बहुत परेशान हो उठी थी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वोटिंग केंद्रों पर बुर्का पहनकर आने की अनुमति से पहचान छिपाने और फर्जी वोटिंग की आशंका बढ़ती है।

देश के सबसे बड़े कारोबारी ग्रुप में सबकुछ ठीक नहीं

अभिनय

बचपन में अगर जब कभी भी कुछ ऐसी मांग कर दी जाती जो मीडिल क्लास के थोड़ा आउट ऑफ बजट हो जाए तो पिताजी फट से बोल पड़ते बड़ा टाटा–बिरला हो गए हो क्या? नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक और चाय से लेकर स्टील तक बनाने वाली 100 अरब डॉलर की कंपनी टाटा एक ऐसा नाम जो हम दशकों से सुनते आ रहे हैं। लोग टाटा का नमक खाते हैं, टाटा की चाय पीते हैं, टाटा के बसों में सफर करते हैं और टाटा की एयरलाइंस में उड़ान भरते हैं। लेकिन फिलहाल टाटा ग्रुप में सबकुछ ठीक नहीं है। रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ग्रप के एडमिनिस्ट्रेशन में परेशानियां नजर आई हैं। ग्रुप फिलाहल आंतरिक कलह को लेकर चर्चा में बना हुआ है। अंदरूनी झगड़ा इतना बढ़ गया है कि अब बात सरकार की चौखट तक पहुंच गई है। गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक बात आ गई है। आज आपको बताते हैं कि टाटा ट्रस्ट के भीतर मचे पूरे बवाल की कहानी क्या है? ताजा झगड़ा किस बात पर है। क्या टाटा ट्रस्ट में चल रही इस कलह ने इस विशाल कारोबारी समूह को खतरे में डाल दिया है? भारत में हर इंसान के लिए टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि टाटा एक भावना है। टाटा का मतलब है विश्वास, टाटा का मतलब भरोसा है। टाटा को वो मजबूत ईंट माना जाता है, जिस पर भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव खड़ी है। 156 साल पुराना ये बिजनेस हाउस जिसकी कीमत आज लगभग 28 लाख करोड़ रुपए है। भारत की इंडस्ट्री और मैन्यूफैक्चरिंग की ६ड़कन है। ऐसे में अगर टाटा ग्रुप के सबसे ऊपरी परत यानी टाटा संस को कंट्रोल करने वाले टाटा ट्रस्ट में कोई खींचतान होती है। उसके सदस्य आपस में झगड़ रहे हैं, आगे क्या करना है उसपर मतभेद है तो इसकी गूंज पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था तक पहुंचेगी। जैसे फुटबॉल के मैच में रेफरी दो बड़े खिलाड़ियों को शांत कराता है। ठीक उसी तरह से मोदी सरकार इस विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस विवाद में लड़ने वाले खिलाड़ी अलग अलग टीम से नहीं बल्कि एक ही टीम के हैं और वो टाटा ग्रप है। टाटा ट्रस्ट्स के बोर्ड में नियुक्तियों और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर समूह के शीर्ष नेतृत्व में चल रहे विवाद को दूर करने की कोशिश जारी है। सूत्रों के मुताबिक टाटा ट्रस्ट बोर्ड की बैठक 10 अक्टूबर को होना प्रस्तावित है। ऐसे में इससे पहले विवाद का समाधान खोजने की तैयारी हो रही है। ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद किया जा रहा है। टाटा ग्रुप का नियंत्रण टाटा ट्रस्ट्स के पास है। इसी के पास टाटा संस में बहुमत की हिस्सेदारी है। टाटा संस वही होल्डिंग कंपनी है. जो करीब 16 लाख करोड़ रु. की रेवेन्यू वाले ग्रुप को नियंत्रण करती है। इसमें टाटा स्टील, टाटा मोटर्स समेत तमाम कंपनियां हैं। दरअसल, इस चका टाटा ट्रस्ट्स का बोर्ड दो खेमों में बंट गया है। पहले गुट में ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा समेत चार और दूसरे में मेहली मिरी, देरियस खांबटा, जाहांगीर और प्रमीत झावेरी शामिल हैं। मेहली की स्व. शान टाटा का करीबी माना जाता था। लेकिन, रतन टाटा के निधन के बाद नोएल को चेयरमैन बनाया गया, तभी से ट्रस्टीज में विवाद है। खबरों के मुताबिक इस अंदरूनी कलह का असर 180 अरब डॉलर के इस बड़े समूह के कामकाज पर पड़ सकता है। इस समूह की विरासत को बचाने के लिए सरकार के हस्तक्षेप पर भी विचार किया जा रहा है। यह स्थिति दिखाती है कि भारत के सबसे सम्मानित व्यापारिक घरानों में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस (कंपनी चलाने का तरीका) कितना नाजुक हो सकता है टीसीएस ने जुलाई–सितंबर तिमाही के नतीजों के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद कर दी। इसकी वजह रतन टाटा की पुण्यतिथि के साथ तारीख का संयोग बताया। 7 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बैठक हुई थी। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित टाटा ट्रस्ट और टाटा संस के सीनियर लीडरशिप लोग शामिल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने इस बैठक में टाटा के घरेलू झगड़ों को जल्द निपटाने के लिए कहा है, जिससे की कंपनी पर कोई बुरा असर न पड़े। इस ग्रुप का कारोबार 100 से ज्यादा देशों में है। इस ग्रुप में 10 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। टाटा ग्रुप में 31 कंपनियां हैं और इसमें से 26 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। आज से एक साल पहले 9 अक्टबर 2024 को ही रतन टाटा की मृत्यु हुई थी। आज रतन टाटा की आज पुण्यतिथी है। यानी रतन टाटा की मृत्यु के एक साल भी अभी पूरे नहीं हुए और टाटा ग्रुप में झगड़े शुरू हो गए और विवाद शुरू हो गए। आज टाटा ग्रुप के टॉप लीडरशिप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रतन टाटा कि इस विरासत को संभाल कर रखने की है।

हिंदू को बांटो, लड़ाओ, खरीदो और बनाओ गंवार!

हरिशंकर व्यास

सोचें, भारत में सामाजिक (हिंदू) समरसता का कौन सा मघॅडल प्रदेश है? मेरा मानना है मध्य प्रदेश! और वहां अभी क्या हल्ला हुआ? भाजपा ने ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 27 प्रतिशत करने के कमलनाथ सरकार के पुराने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद की है कि ष्कांग्रेस कई वर्षों तक सत्ता में रही लेकिन उसने किसी वर्ग के साथ न्याय नहीं किया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। हमें उम्मीद है कि अदालत मध्यप्रदेश में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी देगीष। अर्थात भाजपाध्संघ परिवारः मोहन यादव सरकार राज्य की ओबीसी (51 प्रतिशत), अनुसूचित जाति (एससी) 15.6 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति (एसटी) 21.1 प्रतिशत के तीनों वर्गों की राज्य में कथित 87 प्रतिशत आबादी के अनुपात में आगे आरक्षण का झुनझुनाध्रोडमैप सोचे हुए है। और यह सब मोदी सरकार की 11 वर्षों की राजनीति का नतीजा है। जैसे भी हो सत्ता बनाए रखने की जिद् की इस राजनीति ने कांग्रेस और राहुल गांधी को यदि ष्जितनी आबादी, उतना हकष के एजेंडे की ओर धकेला है तो सुप्रीम कोर्ट तथा जनगणना से भाजपा हिंदू समाज को आगे और बिखेरने वाली है। कैसे? मोदी सरकार 2027 में जनगणना कराएगी। अंग्रेजों की कराई 1931 की जाति जनगणना के लगभग सौ साल बाद स्वतंत्र भारत की पहली बार फिर जाति जनगणना होगी। यह जनगणना जाति के साथ उपजाति, पिछघ्ड़े, अतिपिछड़े जैसे अलग–अलग समूहों के खांचों में होगी। जैसे कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार लिंगायतों को बांटने, हिंदू धर्म से उन्हें अलग करने, लिंगायत के भीतर लिंगायत बनाम वीरशैव का झगड़ा बनाने की कोशिश में है वैसे ही अगली जनगणना में पिछड़ों में अति पिछड़ों का वर्गीकरण भी बनेगा। मतलब अति पिछड़ों के वर्गीकरण में यदि हिंदू जाट की उपजातियों जैसे बैंस, भुल्लर, अटवाल आदि की आर्थिक हैसियत के आगे पिछड़े, अति पिछड़े जाट के समूह बने तो आश्चर्य नहीं होगा! क्योंकि जाति जनगणना के पीछे एकमेव मंत्र 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले हिंदुओं को इतना और बांटना है कि मोदी नए वर्ण विभाजन के फार्मूलों में योजना, स्कीम बना कर लोगों के खाते में पैसे डालने के नए फैसले ले सकें, जिससे वोट पके। मतलब ताजा बिहार मॉडल की तरह 2029 में अखिल भारतीय स्तर पर बांटो, लडाओ (जातीय पहचान–हक–आरक्षण की भूख में) के साथ स्कीमों व आरक्षण के जरिए वोट पटाने का महाअभियान! मतलब राहुल गांधी, कांग्रेस, तेजस्वी याकि जातीय–क्षेत्रिय राजनीति के धुरंधरों की पिछड़ा–दलित–आदिवासी राजनीति को जनगणना और उसके बाई प्रोडक्ट की योजनाओं–घोषणाओं–झांसों के महाप्रोपेगेंडा से खारिज करा देना। भयावह सिनेरियो है। मगर अंग्रेजों ने जैसे 1905 में बंग–भंग से बीज बो कर 1947 में हिंदू–मुस्लिम विभाजन तय कराया वैसे नरेंद्र मोदी दिल्ली के वे आखिरी हिंदू शासक संभावी हैं, जिनकी जातीय जनगणना और जातीय आरक्षण की आग में हिंदू राष्ट्रवाद वैसे ही मिट्टी में मिलेगा देने जैसे पृथ्वीराज चौहान के आखिरी शासन की आखिरी हिंदू सत्ता थी! विदेशी गुलामी से पहले की! सोचें, हिंदू मोदी राज में कैसा–क्या है? आरक्षण व्यवस्था लागू होने के 75 वर्ष बाद भारत का दलित चीफ जस्टिस, दलित आईपीएस एडीजीपी, एक दलित कांस्टेबल की हालिया प्रतिनिधि घटनाओं, व्यवहार, अनुभव से क्या यह नहीं मालूम होता कि आरक्षण व्यवस्था पूरी तरह फेल है! इसने हिंदू समाज में समानता की बजाय समरसता, परस्पर मान–सम्मान, सद्भावपूर्ण व्यवहार को न केवल और खराब किया है, बल्कि जातीय पूर्वाग्रहों, वैमनस्य, दुराव, नीचताओं की हद पार करा दी है। सचमुच हर हिंदू को (ष्जितनी आबादी, उतना हकघ्ष का सामाजिक न्याय चाहने वालों को अवश्य) हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस एडीजीपी पुरण कुमार के सुसाइड नोट तथा घटना के बाद उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी अनमित कुमार की शिकायत–एफआईआर को पढ़ना चाहिए। समझ आएगा कि आरक्षण की व्यवस्था ने हिंदू समाज को मानसिक उत्पीडन की भत्र्ठी बना दिया है। पूरा समाज, पूरी आबादी जल रही है, खोखला गई है।

विभाजक ताकतों को उलाहना देती बाबुश्किन की हिंदी

उमेश

आज के रूस और उसके पूर्ववर्ती सोवियत संघ में हिंदी की पढ़ाई–लिखाई 1957 से ही शुरू हो गई थी, इस लिहाज से रूस के किसी नागरिक का हिंदी बोलना महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। लेकिन आज के दौर में भारत स्थित रूसी दूतावास के दूसरे नंबर के अधिकारी रोमन है, जो हिंदी का सवाल आते ही भड़क उठते हैं। जिन्हें विदेशी अंग्रेजी तो ग्राह्य और स्वीकार्य है, लेकिन हिंदी उनकी अपनी अस्मिता पर सवाल उठाती लगती है। आजाद भारत की राजनीति जाति, धर्म और भाषा के आधार पर किस कदर विभाजित हुई है, इसे समाज तो रोज ही झेलता–देखता है। इस विभाजक सोच

बाबुश्किन अगर हिंदी के चंद लफ्जों का इस्तेमाल करें तो वह अहम हो जाता है। रूस से तेल खरीद के चलते अंकल सैम की आंखें इन दिनों भारत पर लाल हैं। इसी संदर्भ में 20 अगस्त को रूसी दूतावास ने एक प्रेस कांफ्रेंस रखी। उस प्रेस कांफ्रेंस में अपने संबोधन की शुरूआत बाबुश्किन ने हिंदी के दो वाक्यों से करके भारतीय भाषा प्रेमी पत्रकारों का दिल जीत लिया। बाबुश्किन का पहला वाक्य रहा, 'सभी का हार्दिक स्वागत है।' पत्रकारिता जगत की हस्तियों की श्रवणेंद्रिय इस हिंदी प्रयोग का झटका झेल रही थीं, कि बाबुश्किन ने ठेठ भारतीय सांस्कृतिक अंदाज में दूसरा वाक्य छोड़ दिया, ष्हम शुरुआत करेंगे. ..भगवान गणेश के साथ। गणेश चतुर्थी आ रही ह बाबुश्किन का हिंदी बोलना भारतीय राजनीति और समाज के उस तबके के लिए सीख हो सकता का ही असर है कि हमारी अपनी भाषाओं के बीच भी झगड़े पैदा किए जा रहे हैं। भारतीय भाषाओं को एक–दूसरे के विरोध में राजनीति खूब खड़ा कर रही है और इसके जरिए वह अपना सियासी उल्लू ही सीधा करती है। नैरंतर्य और सकारात्मकता के लिहाज से देखें तो इसके सामाजिक विघटन की नींव ही मजबूत हो रही है। अस्मिताबोध को जगाने की आड़ में भाषायी वैमनस्य की राजनीति का एक मात्र मकसद सामाजिक विघटन को बढ़ाना और उस बंटे समाज के बीच से अपने खांचे में फिट बैठने वाला बड़ा समर्थक आधार वर्ग तैयार करना है। इसीलिए जब नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के जरिए प्राथमिक शिक्षा की बात होती है तो हिंदी को किनारे लगाने के लिए तमिल राजनीतिक अस्मिता उठ खड़ी होती है। कन्नड़ और बांग्ला भाषा बोध भी हिंदी के खिलाफ उठ खड़ा होता है। दिलचस्प यह है कि स्थानीय भाषाबोध के इन खिलाड़ियों के लिए वह अंग्रेजी अपनी हो जाती है, जिसकी कथित तौर पर वैश्विक व्यापकता है। हालांकि हकीकत यह है कि अंग्रेजी की व्यापकता गहराई से देखें तो अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और हांगकांग में ही है। अंग्रेजी को तो बाबुश्किन ने भी अपना रखा है। भारतीय पत्रकारों के लिए आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बाद में वे अंग्रेजी में ही बोले। लेकिन हिंदी में बोलकर उन्होंने एक तरह से भारतीय लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। ठीक उसी अंदाज में, जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी स्थानीय समुदायों के दिल तक अपनी पैठ बनाने के लिए स्थानीय भाषाओं के कुछ शब्दों के साथ अपने भाषण की शुरुआत करते रहे हैं। पता नहीं, बाबुश्किन ने हिंदी बोलकर वहां उपस्थित कितने भारतीय पत्रकारों का दिल जीता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और सोशल मीडिया पर जब से उनकी मीठी प्रचारित हुई है,उन्होंने ठेठ भारतीयों का दिल जरूर जीत लिया है। सोवियत संघ में हिंदी फिल्में काफी पसंद की जाती रही हैं। एक दौर में राजकपूर की फिल्में खासा लोकप्रिय रही हैं। राजकपूर अभिनीत फिल्म श्री 420 का गीत 'मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' एक दौर में सोवियत संघ के घर–घर का पसंदीदा गीत बन गया था। कम्युनिस्ट शासन के दौर में रूस की राजधानी मास्को में हिंदी में दो प्रकाशक भी सक्रिय रहे, प्रगति प्रकाशन और रादुगा प्रकाशन। इन प्रकाशनों के जरिए रूसी लेखकों के साथ ही लेनिन, स्टालिन आदि की रचनाएं हिंदी में अनूदित होकर सस्ते में उपलब्ध होती थीं। एक दौर में सोवियत संघ की दो पत्रिकाएं 'सोवियत देश' और श्स्पूतनिक' भारत में बहुत प्रचलित थे। हिंदी की वहां पढ़ाई भी खूब होती है। इसकी शुरूआत 1955 में हुई। उसके पहले तक रूस की भारत में दिलचस्पी संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन तक सीमित थी। साल 1955 में सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री निकिता ख्रुश्चेव ने भारत का दौरा किया। इसी दौरे में उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, ष्हम यह देखेंगे कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली ऐसी विकसित हो जिसमें सर्वश्रेष्ठ और सर्वगुण–सम्पन्न नई पीढ़ी हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को सीखें।ष्इसी के बाद सोवियत संघ में हिंदी प्रकाशन और पढ़ाई–लिखाई की शुरूआत हुई। आज रूस के मास्को राजकीय विश्वविद्यालय, रूसी राजकीय मानविकी विश्वविद्यालय, अंतरराष्ट्रीय संबंध विश्वविद्यालय, सांक्त पितेरबूर्ग विश्वविद्यालय, विद्यालय क्रमांक 19, मॉस्को, फार ईस्ट विश्वविद्यालय, ब्लादीवोस्तक आदि में हिंदी पढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के जवाहरलाल नेहरू साँस्कृतिक केंद्र में हिन्दी की कक्षाएँ चल रही हैं। जिनमें हर आयु वर्ग लोग हिंदी सीख रहे हैं। साफ है कि विदेशी लोग हिंदी सीख रहे हैं, भारत आए विदेशी हिंदी बोल रहे हैं। इस्कॉन के मंदिरों में जाकर देखा जा सकता है, भगवान कान्हा के विदेशी भक्त भी मीठी हिंदी में बात करते मिल जाएंगे। लेकिन हमारी ही राजनीति के ही एक वर्ग को हमारी हिंदी से परहेज है। ऐसे लोगों के लिए बाबुश्किन की मीठी हिंदी एक तरह मीठा उलाहना है।

भाजपा ने बिहार खरीदा, जीत लिया!

हरिशंकर व्यास

हो सकता है मैं गलत हूं, फिर भी मेरा मानना है बिहार मोदी–शाह की गोद में है। तेजस्वी, राहुल गांधी, प्रशांत किशोर किसी का कोई अर्थ नहीं। इन सबकी याकि विपक्ष की दिक्कत है जो नहीं समझते कि नरेंद्र मोदी–अमित शाह चौबीस घंटे सत्ता की भूख में जीते हैं। कैसे भी हो सत्ता में रहना है। सोचें, ईस्ट इंडिया कंपनी के बनिया अंग्रेज और मोदी–शाह में क्या समानता है? फूट डालो, राज करो और खरीदो! त्रासद है उस इतिहास को याद कराना। पर तथ्य याद करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में पलासी और 1764 में बक्सर के युद्ध को जीता था तो उसमें तब बिहार भी था। पता है क्लाइव की सेना में कुल तीन हजार सैनिक थे! इसमें गोरे सैनिक केवल आठ सौ थे! जबकि हिंदुस्तानी सेना में पचास हजार सैनिक थे। मगर क्लाइव ने स्थानीय जगत सेठों के पैसे का इस्तेमाल किया। मीर जाफर और उनके सैनिकों को खरीद लिया। सो, अंग्रेज बनिया जीते और फिर दो सौ साल बंगाल, बिहार और उड़ीसा को लूटा। सो, बांटना, जीतना, लूटना अंग्रेजों का बताया मंत्र है। भला मोदी–शाह की ईस्ट इंडिया कंपनी याकि क्रोनी जगत सेठों के हिस्सेदारी वाली कंपनी क्यों चूके? ध्यान रहे बिहार को मोदी–शाह की टीम ही चला रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जनता दल यू पूरी तरह मोदी–शाह की राजनीति, प्रबंधकीय व्यवस्थाओं, वोट पकाने की असेंबली लाइन से निर्देशित हैं। मैंने 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद विश्लेषण किया था कि चुनाव का मतदान अब मोदी–शाह की असेंबली लाइन में धड़ाधड़ वोटों का उत्पादन है। इसलिए क्योंकि दोनों की गणित में ए टू जेड के सभी विकल्प हैं, जुमले हैं, प्रबंधकीय व्यवस्थाएं हैं। और यह सत्य लगातार साबित हुआ है। बिहार के मामले में अपने को इसलिए दिलचस्पी थी क्योंकि प्रशांत किशोर बिहार और मोदी–शाह को गहराई से जानते–समझते हैं तो वे कुछ ऐसा नया, अनहोना करेंगे जिससे कुछ उलटफेर हो। पर वे भी फेल होते लगते हैं। इसलिए क्योंकि उन्हें यह अनुमान नहीं रहा होगा कि चुनाव से ऐन पहले लगभग पूरी आबादी को अलग–अलग टुकड़ों में बांट, उनके अलग–अलग प्रतिनिधि ग्रुप बनाकर सीधे खातों में इतनी नकदी पहुंचा दी जाएगी कि घर–परिवार के लोग बाकी सब भुला देंगे। मेरा मानना है महिलाओं के खातों में दस हजार रुपए की नकदी पहुंचाना निर्णायक है। जिस प्रदेश में कुछ सौ रुपए, हजार–दो हजार रुपए के लिए लाठी चले, जान चली जाए वहां दस–दस हजार रुपए महिला के खाते में पहुंचे और उस पैसे से छठ का त्योहार मने तो वह तो उनके लिए अमृतकाल ही होगा! कहते हैं इतनी स्कीमों, इतने बहानों की आड़ में सरकार से बिहार में पैसा बंटा है कि कोई हिसाब नहीं लग सकता। तभी ईवीएम से कथित धांधली या चुनाव आयोग की हेराफेरी या हिंदू बनाम मुस्लिम की बिहार में जरूरत नहीं होगी। बिहार का यह चुनाव सरकारी पैसे से जीता जाएगा। चुनाव में वादों से पहले ही जब पैसा बंट गया है।

शहर से लेकर ग्रामीण थाना क्षेत्रों मे पुलिस अभियान चलाकर बरामद कर रही अवैध पटाखे

अयोध्या।थाना पूराकलंदर क्षेत्र मे गुरुवार को हुई विस्फोट से जिले मे सभी थाना क्षेत्रों की पुलिस प्रशासन कुंभकर्णी नींद से जाग कर अवैध पटाखों व विस्फोटक सामग्रियों का भण्डारण करने वाले कारोबारियों पर शिकंजा कसने मे जुटी हुई है।जिले के सभी थाना क्षेत्र में छापा मारा अभियान चलाया जा रहाहै।एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी व एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी के निर्देश पर सभी सर्किल के सीओ अपने अपने क्षेत्र में थानाध्यक्षों के साथ अवैध रूप से पटाखे व आतिशबाजी बनाने वाले सामग्रियो की बरामदगी के लिए सघन छापामारी अभियान चलाया जा रहा है।आज रविवार को भी इनायत नगर तथा खंडासा पुलिस ने छापा मार कर भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किया।जबकि शनिवार को कोतवाली नगर क्षेत्र के अलावा थाना कैंट पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखों को बरामद किया।सिटी शैलेन्द्र सिंह की देखरेख में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अश्वनी पाण्डेय के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा शहर के चौकी क्षेत्र अलीगढ़ के रीडगंज मोहल्ले से भारी मात्रा मे पटाखे बरामद किया गया।कोतवाली नगर पुलिस ने इसमें शामिल तीन महिला आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया जिनकी पहचान महर अफरोज उर्फ माया पत्नी अब्दुल लतीफ निवासी रीडगंज थाना कोतवाली नगर,हमीदा पुत्री स्वर्गीय मोहम्मद मुराद निवासी रीडगंज थाना कोतवाली नगर व राशिदुल निशां पत्नी स्वर्गीय मोहम्मद रज्जु निवासी रीडगंज थाना कोतवाली नगर के रूप में हुई।पुलिस ने इनके पास से अनार, सुतली बम, बिजली बम, लड्डू बम, ग्राउण्ड स्पिनर (चकरी), थण्डर बम, फुलझड़ी, राकेट बम व श्री शाट (फोर शाट ६ टेन शाट अन्य पटाखे, हन्टर बम पटाखा, बुलेट बम आदि बरामद किया। इस सफलता मे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अश्विनी कुमार पाण्डेय के अलावा चौकी चौक प्रभारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा,उ०नि० धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना को० नगर,विकास गुप्ता,उ0नि0 संतोष मौर्य थाना को० नगर जनपद,म०उ०नि० किरन पाल थाना को० नगर जनपद,कां० अमित कुमार थाना को० नगर व म०कां० दीपांशी शर्मा थाना को० नगर शामिल भूमिका रहे।थाना कैण्ट पुलिस टीम ने अवैध पटाखों के साथ एक आरोपी राजदीप मौर्या पुत्र मनोज कुमार मौर्या निवासी मस्तान का पुरवा थाना कैण्ट को मस्तान का पुरवा से भारी मात्रा में अवैध पटाखा एवं आतिशबाजी की सामग्री के साथ गिरफ्तार किया।गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम मे प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट पंकज कुमार सिंह थाना कैण्ट के अलावा चौकी प्रभारी सहादतगंज अविनाश त्रिपाठी,उ0नि0 मनीष कुमार थाना कैण्ट,उ0नि0 आदर्श विक्रम सिंह थाना कैण्ट सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।आज रविवार को हुई कार्यवाही के संबंध में सीओ सिल्कीपुर श्रेयश त्रिपाठी ने बताया कि इनायत नगर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखों को बरामद करते हुए मौके से आरोपी मकसूद उर्फ पप्पू पुत्र मोहम्मद मुस्तफा निवासी ग्राम सेमरा थाना इनायत नगर को डाकखाना वाली गली हरिगंटगंज बाजार से तथा खंडासा थाना पुलिस।

खाना खाते ही मुंह से निकला झाग, रावत मंदिर के महंत ने तोड़ा दम

लखनऊ, (संवाददाता)। रामनगरी अयोध्या में रावत मंदिर के महंत राममिलन दास की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया गया कि रात में भोजन करने के कुछ देर बाद महंत की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मुंह से झाग निकलने लगा। यह देख शिष्यों ने तुरंत उन्हें श्रीराम अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना पर अयोध्या कोतवाली प्रभारी मनोज शर्मा मौके पर पहुंचे। मामले की जांच की जा रही है। वहीं, दिगंबर अखाड़ा के महंत रामलखन दास और वामन मंदिर के महंत

वैदेही बल्लभ शरण भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की। शिष्यों का कहना है कि महंत राममिलन दास सरल और धार्मिक स्वभाव के संत थे। वे पिछले 15 वर्षों से रावत मंदिर के महंत के रूप में सेवाएं दे रहे थे। उनके गुरु राममिलन दास राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख अगुवाओं में से एक रहे थे। सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में मंदिर से जुड़ी जमीन की बिक्री से करीब छह से सात करोड़ रुपये उनके खाते में आए थे। घटना की जानकारी पर डीएम निखिल टीकाराम फुंडे और एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर भी अस्पताल पहुंचे। हालांकि अब तक मौत के कारणों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है।

संक्षिप्त खबरें

डीआईओएस आफिस मे छात्रों के पंजीकरण फार्म के साथ-साथ संबंधित कश्वलेजों की मान्यता की हो रही जांच

अयोध्या।हाई व इंटर परीक्षा मे शामिल होने के लिए कालेजों मे पंजीकृत छात्रों के डीआईओएस कार्यालय में रजिस्ट्रेशन तभी संभव है जब संबंधित विषय की मान्यता संबंधित कॉलेज के पास हो। प्राय यह देखा जाता था कि कुछ ऐसे कालेजों के प्रबंध तंत्रो तथा प्रधानाचार्य द्वारा बिना मान्यता के तथा विषय के छात्रों का पंजीकरण करके हाई स्कूल व इंटर बोर्ड परीक्षा में शामिल कराते थे।उस पर अंकुश लगाने के लिए शिक्षा विभाग अब यह कदम उठाया है।इस बार जिन कालेजों को हाई स्कूल व इंटर में जिस विषय की मान्यता मिली है,उसी विषय से संबंधित छात्र परीक्षा दे सकते हैं।इसके साथ ही साथ जिन कॉलेजों को जिस माध्यम से हिंदी हो या चाहे अंग्रेजी इस माध्यम के छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।इसके लिए शासन के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में इस संबंध में विभिन्न कॉलेजों से हाई स्कूल व इंटर के छात्रों की रजिस्ट्रेशन हेतु फॉर्म आ रहे हैं।उसके लिए मान्यता संबंधित कागजात भी लाने होंगे।डीआईओएस ऑफिस में विभिन्न कॉलेजों से हाई स्कूल व इंटर के छात्रों की रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे फॉर्म का जांच बारीकी से किया जा रहा है।डीआईओएस कक्ष में इन फार्मो को बारीकी से जांच तो किया ही जा रहा है साथ ही साथ जिन कॉलेजों से पंजीकृत छात्रों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जांच किया जा रहा है।उसके साथ ही साथ उक्त कालेज के मान्यता के कागजात को भी देखा जा रहा है। इसके लिए डॉक्टर पवन कुमार तिवारी ने एक टीम का गठन किया है।जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज दादेरा के प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार,उप प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज अयोध्या राजेश शुक्ला,मनोज दूबे शामिल है।

फीनिक्स यूनाइटेड, लखनऊ में करवा चौथ का रंगीन उत्सव'

'लखनऊ, 13 अक्टूबर, 2025रू' त्योहारों के इस खुशनुमा मौसम में फीनिक्स यूनाइटेड मॉल, लखनऊ ने शहर की महिलाओं के लिए करवा चौथ को और खास बना दिया। हर साल की तरह इस बार भी फीनिक्स ने अपने महिला ग्राहकों को प्रेम, स्नेह और स्वयं के शृंगार का खूबसूरत पल देने का प्रयास किया। दो दिनों तक चले इस विशेष आयोजन 9 और 10 अक्टूबर में मॉल में करवा चौथ थीम पर सजा हुआ रंगीन सेटअप आकर्षण का केंद्र रहा। महिलाओं ने पारंपरिक मेहंदी कला का आनंद लिया और एक अनुभवी विशेषज्ञ द्वारा की गई मेकअप मास्टरक्लास में हिस्सा लिया। इस सत्र में उपस्थित महिलाओं ने फेस्टिव मेकअप और स्किनकेयर से जुड़ी कई उपयोगी बातें सीखीं। फीनिक्स यूनाइटेड मॉल ने इस आयोजन के माध्यम से न केवल त्योहार की पारंपरिक भावना को जीवंत किया बल्कि अपनी महिला ग्राहकों को खुद को बेहतरीन ढंग से संवारने और उत्सव की तरह मनाने का अवसर भी दिया। फीनिक्स मिल्स के रीटेल डायरेक्टर (नॉर्थ) श्री संजीव सरीन ने कहा, "फीनिक्स यूनाइटेड हमेशा से अपने ग्राहकों को सिर्फ शॉपिंग से बढ़कर एक यादगार अनुभव देने में भरोसा रखता है। करवा चौथ जैसे त्योहार हमारे लिए रिश्तों और खुद्द को एक्सप्रेस करने का उत्सव हैं, और हम हर साल इसे और खास बनाने की कोशिश करते हैं।" फीनिक्स यूनाइटेड ने करवा चौथ के इस उत्सव के साथ ही फेस्टिवल सीजन की आकर्षक शुरुआत भी की है।

महिलाओं के हुनर को मिला मंच

लखनऊ, (संवाददाता)। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (जीतो) लखनऊ चौप्टर की ओर से पहली बार दो दिवसीय जैन कार्निवाल दीपावली मेले का आयोजन शनिवार को मोती महल लॉन में किया गया। मेले का शुभारंभ औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने किया। दोनों ने हर स्टॉल पर जाकर वहां प्रदर्शित उत्पादों की जानकारी ली। इसके बाद उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी स्टॉलों का अवलोकन किया और महिलाओं के प्रयासों की सराहना की। जीतो महिला विंग की अध्यक्ष डॉ. अमिता जैन ने बताया कि जीतो संगठन 32 देशों में सक्रिय है और लखनऊ देश का 77वां चौप्टर बना है। जीतो लखनऊ चौप्टर के महामंत्री अभिषेक जैन ने बताया कि मेले का उद्देश्य उन महिलाओं को मंच देना है जो घर से काम तो कर रही हैं पर उनकी प्रतिभा लोगों के सामने नहीं आ पाई थी। मेले में 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए, जिनमें महिलाओं ने हस्तनिर्मित उत्पाद जैसे जूलरी, सजावट के समान, सोलर पैनल और पौष्टिक लड्डू जैसी विविध वस्तुएं प्रदर्शित कीं। आयोजन स्थल पर पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल भी रहे। मिक्की जैन ने अपने आर्टिफिशियल जूलरी के स्टॉल से लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने बताया कि उनके पति 18 साल से पैरालाज्ड हैं। पहले वह जूलरी का काम करते थे। मिक्की बताती हैं कि वह घर से ऑर्डर लेकर और प्रदर्शनियों में भाग लेकर अपना और पति दोनों का खर्च चला रही हैं। चौक निवासी पारुल को पौष्टिक लड्डू बनाने का शौक है। उन्होंने बताया कि वह ऑर्डर मिलने पर विभिन्न प्रकार के पौष्टिक लड्डू तैयार करती हैं। आधा किलो लड्डू की कीमत 600 रुपये है। पारुल ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रदर्शनी में स्टॉल मिलने से मेहनत में मिठास आ गई है। रेनू कौर ने अपशिष्ट पदार्थों से सुंदर दीये, पॉट्स, वॉल हैगिंग्स, मनी एनवेलप और सजावटी वस्तुएं तैयार कर लोगों को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि बिना किसी आर्थिक मदद के यह काम करती हैं और अपने उत्पादों को ऑनलाइन व प्रदर्शनियों में बेचती हैं। उन्होंने अपनी रचनात्मकता से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। गोमतीनगर निवासी नेहा ने सोलर पैनल का स्टॉल लगाया। उन्होंने बताया कि पहले वह टेलीकॉम सेक्टर में काम करती थीं, लेकिन पति के निधन के बाद सोलर पैनल का बिजनेस शुरू किया। आज कई घरों में उनके लगाए पैनल बिजली बचा रहे हैं।

कुर्सी रोड बेहटा से लेकर टेढ़ी पुलिया चौराहे तक सड़क को सिक्स लेन करने की रक्षामंत्री से गुहार

लखनऊ – ग्रेटर लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष रूप कुमार शर्मा व महासचिव विवेक शर्मा ने आज रक्षामंत्री के प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी से मिल कर कुर्सी रोड बेहटा से लेकर टेढ़ी पुलिया चौराहे तक सड़क को सिक्स लेन करने के लिए एक पत्र सौंपा। इसके पूर्व ग्रेटर लखनऊ जनकल्याण महासमिति मुख्यमंत्री व मण्डलायुक्त को भी कुर्सी रोड बेहटा से लेकर टेढ़ी पुलिया चौराहे तक सड़क को सिक्स लेन करने हेतु पत्र लिख मांग कर चुकी है। कुर्सी रोड पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है तथा भविष्य में कुकरैल वन में नाइट सफारी भी प्रस्तावित है और यातायात वाहनों की संख्या भी काफी बढ़ेगी। फोर लेन (डिवाइडेड कैरिजवे) के अनुसार सड़क पी०सी०यू० 18000 से 35000 तक प्रतिदिन का है, किंतु राज्य राज मार्ग के कुर्सी रोड पर वर्तमान में वाहनों का आवागमन प्रतिदिन लगभग 1 लाख से अधिक वाहनों का आवागमन होता है। इसलिए क्षेत्रवासियों को भविष्य में होने वाली जनसमस्या का पूर्व में ही व्यापक स्तर पर व्यवस्थित करने तथा कुर्सी रोड को सिक्स लेन किया जाना ज्यादा उचित होगा। कुर्सी रोड राज्य राजमार्ग को पी०सी०यूव (पेमदहमत बंत न्दपज) के मानक के अनुसार सड़क चौड़ीकरण के मानक सड़क की गति, यातायात की मात्रा, और आसपास के भूभाग के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इसमें कैरिजवे की चौड़ाई का निर्धारण होता है, जो वाहन की चौड़ाई और आवश्यक निकासी के आधार पर होता है। तीव्र मोड़ों पर सुरक्षित मार्ग के लिए कैरिजवे को चौड़ा करना पड़ता है, जबकि आवासीय क्षेत्रों में दो व्हील चेयर पार करने के लिए पर्याप्त जगह देने के लिए फुटपाथ की चौड़ाई 1.8 मीटर और वाणिज्यिक क्षेत्रों में 2.5 मीटर न्यूनतम होनी चाहिए। वर्तमान में कुर्सी रोड चार लेन की है तथा अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। सरकार द्वारा कुकरैल वन में नाइट सफारी प्रस्तावित है एवं अन्य विकास परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी कुर्सी रोड पर प्रगति पर है। आने वाले समय में वाहनों की संख्या बढ़ेगी तथा सड़क पर जाम की स्थिति भी उत्पन्न होगी। ग्रेटर लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष रूप कुमार शर्मा तथा महासचिव विवेक शर्मा बताया कि कुर्सी रोड को सिक्स लेन करने मांग पर सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी ने सर्वेक्षण कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। महासमिति ने अभिषेक मेमोरियल पार्क, विवेक खण्ड 4, गोमतीनगर में ओपन जिम लगवाने हेतु भी एक पत्र दिवाकर त्रिपाठी को सौंपा।

संक्षिप्त खबरें

भातखंडे विवि में दो छात्र गुटों में मारपीट, एक का सिर फूटा, तीन निलंबित, कमेटी गठित

लखनऊ, (संवाददाता)। कैसरबाग स्थित भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में शनिवार शाम दो छात्र गुटों में जमकर मारपीट हुई। एक छात्र का सिर फट गया। इस मामले में कैसरबाग थाने में तहरीर भी दी गई। विवि प्रशासन ने छात्रों के अभिभावकों को बुलाया तो दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया, लेकिन कुलपति प्रो. मांडवी सिंह ने देर शाम मारपीट के आरोपी तीन छात्रों को निलंबित कर दिया। उन्होंने कमेटी का भी गठन किया है। विवि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विवि परिसर में पैसों के लेन देन पर यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे संगीत डिप्लोमा के छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें एक छात्र का सिर फट गया। कैसरबाग कोतवाली के इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि तहरीर दी गई थी। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। वहीं, कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय में इस प्रकार की मारपीट की घटना पहली बार प्रकाश में आई है। जिस समय मारपीट हुई, उस समय मैं विश्वविद्यालय में मौजूद नहीं थी। वापस आने पर मारपीट की जानकारी मिली। तत्काल अनुशासनात्मक कमेटी का गठन कर दिया गया है। तीन छात्रों को निलंबित भी कर दिया गया है।

उच्च शिक्षा के लिए सरकारी खर्च पर भेजे जाएं केजीएमयू के डॉक्टर

लखनऊ, (संवाददाता)। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने डीएम–एमसीएच जैसे उच्च शिक्षा के कोर्सों की पढ़ाई करने वाले शिक्षकों को सरकारी खर्च पर भेजने की मांग की है। शिक्षक संघ की आम सभा की बैठक में शनिवार को इसके साथ अन्य मुद्दे भी उठाए गए। संघ के सचिव प्रो. संतोष कुमार ने बताया कि केजीएमयू में स्टडी लीव की सुविधा नहीं है। इस वजह से शिक्षकों को अपने खर्च पर वेतनरहित अवकाश लेना पड़ता है, जबकि सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को सरकारी खर्च पर यह सुविधा मिलती है। इसके एवज में उन्हें बॉन्ड भरना होता है। केजीएमयू के शिक्षकों को भी यह सुविधा मिले। संघ के अध्यक्ष प्रो. केके सिंह का कहना है कि ऐसा होने पर वे मरीजों के इलाज में और बेहतर सहयोग कर सकेंगे। बैठक में संघ के नामित सदस्यों तथा बाइलॉज में मामूली संशोधन पारित हुए। शिक्षकों ने समस्याएं दूर न होने पर दीपावली के एक माह बाद दोबारा आम सभा बुलाने का फैसला किया है। इसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी।

क्विज प्रतियोगिता में बच्चियों ने दिखाई प्रतिभा

लखनऊ, (संवाददाता)। मिशन शक्ति के तहत अस्तित्व फाउंडेशन की ओर से प्राथमिक विद्यालय अलीगंज में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इसमें कक्षा एक से पांच तक बेटियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की आयोजक एमिटी विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर व अस्तित्व फाउंडेशन संस्थापक सदस्य डॉ. प्रिया गुप्ता ने बताया कि बच्चियों को बालिका दिवस के बारे में बताया गया। क्विज प्रतियोगिता में बच्चियों ने प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह, महिला उपनिरीक्षक, आशि गुप्ता और प्रगति सिंह ने बालिकाओं को सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी।

26 लाख दीयों से जगमगाएगी पावन नगरी, यूपीएसटीडीसी ने लखनऊ से विशेष यात्रा पैकेज की घोषणा

लखनऊ, (संवाददाता)। भगवान श्रीराम की पावन नगरी अयोध्या इस दीपावली 26 लाख दीयों से जगमगाने को तैयार है। दीपोत्सव–2025 के इस भव्य अवसर पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए लखनऊ से अयोध्या तक एक दिवसीय विशेष यात्रा पैकेज की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) द्वारा संचालित यह कम दर का पैकेज यात्रियों को दीपोत्सव के अद्भुत नजारों का साक्षी बनने का अवसर प्रदान करेगा।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री डॉ. जयवीर सिंह ने बताया कि दीपोत्सव यात्रा की शुरुआत 19 अक्टूबर को होगी। सुबह 11 बजे लखनऊ स्थित होटल गोमती से टेम्पो ट्रैवलर यात्रियों को लेकर अयोध्या के लिए रवाना होगा। मार्ग में दोपहर 2रू30 बजे भोजन की व्यवस्था की गई है। शाम 3 बजे यात्रा दल अयोध्या पहुंचेगा और राम की पैड़ी पर दीपोत्सव समारोह का साक्षी बनेगा।इस यात्रा का शुल्क 1,500 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया है, जिसमें ट्रांसपोर्ट, स्थानीय गाइड, दिन–रात के भोजन और पानी की बोतल की सुविधा शामिल है। इच्छुक यात्री पैकेज की ऑनलाइन बुकिंग यूपीएसटीडीसी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं।डॉ. जयवीर सिंह ने बताया कि शाम 7रू30 बजे पावन सरयू तट पर 26 लाख से अधिक दीयों को प्रज्वलित होते देख यात्रियों को भव्य दृश्य का अनुभव होगा। इस दौरान आकाश में रंग–बिरंगी आतिशबाजी, आकर्षक लेजर शो और एरियल ड्रोन प्रस्तुति दीप्तिमान माहौल बनाएगी। मनमोहक दृश्य का आनंद लेने के बाद रात्रि 9रू30 बजे भोजन कराया जाएगा और रात 11 बजे यात्रा दल लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगा।मंत्री ने कहा कि अयोध्या दीपोत्सव केवल वार्षिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक आस्था और भारतीय परंपरा को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने वाला उत्सव है। यूपीएसटीडीसी द्वारा तैयार यह विशेष यात्रा कार्यक्रम श्रद्धालुओं को अयोध्या की आध्यात्मिकता और भव्यता का साक्षी बनने का अवसर देगा। समूह में यात्रा करने से श्रद्धालुओं को सामाजिक मेलजोल और संवाद का भी अवसर प्राप्त होगा, जिससे उत्तर प्रदेश की पहचान आस्था पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में और सुदृढ़ होगी।

मायावती ने हरियाणा आत्महत्या प्रकरण पर जताया आक्रोश

लखनऊ, (संवाददाता)। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हरियाणा में आईजी रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की आत्महत्या की घटना को अत्यंत दुखद, गंभीर और शर्मनाक बताते हुए कहा कि इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मायावती ने कहा कि यह घटना न केवल दलित समाज बल्कि पूरे बहुजन वर्ग को गहरे तौर पर उद्वेलित करने वाली है और यह स्पष्ट करती है कि शासन–प्रशासन के उच्च स्तर तक जातिवाद का जहर अब भी फैला हुआ है।मायावती ने अपने बयान में कहा कि वाई. पूरन कुमार, जो हरियाणा पुलिस में आईजी रैंक के अधिकारी थे और जिनकी पत्नी स्वयं राज्य की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने जातिवादी शोषण और प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर ली। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि सरकारों के तमाम दावों के बावजूद जातिवाद का दंश अब भी प्रशासनिक ढांचे में गहराई तक मौजूद है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति एक सभ्य सरकार और संवेदनशील समाज के लिए अत्यंत शर्मनाक है।बसपा सुप्रीमो ने मांग की कि इस प्रकरण की समयबद्ध, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोबारा न हों। उन्होंने चेतावनी दी कि हरियाणा सरकार को इस घटना की लीपापोती करने या खानापूर्ति करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जैसा कि शुरुआती आरोप सामने आ रहे हैं। मायावती ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को भी उचित संज्ञान लेकर न्याय सुनिश्चित करना चाहिए।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत प्रदेशभर में आयोजित

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह (3 से 11 अक्टूबर) के अवसर पर प्रदेशभर में आज 'ष्शक्ति संवाद' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस पहल का उद्देश्य लाभार्थी बालिकाओं और महिलाओं को योजनाओं के प्रभाव और उनके अनुभव साझा करने का मंच प्रदान करना था।जनपद स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड एवं सामान्य), पति की मृत्यु उपरांत महिला पेंशन योजना जैसी प्रमुख योजनाओं की लाभार्थी बालिकाओं और महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे और संवाद की श्रृंखला में लाभार्थियों ने अपनी समस्याएँ, अनुभव और योजनाओं से जुड़े सुझाव साझा किए।अधिकारियों ने लाभार्थियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि आवश्यकतानुसार हर संभव सहायता समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाएगी। इस पहल से बच्चों और महिलाओं की वास्तविक जरूरतें सीधे प्रशासन तक पहुँच सकीं, जिससे योजनाओं का लाभ अधिक पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ मिल सके।अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग लीना जोहरी ने कहा कि 'ष्शक्ति संवाद' केवल योजनाओं की जानकारी या समीक्षा का मंच नहीं है, बल्कि यह उन बालिकाओं और महिलाओं की आवाज को सम्मान देने का प्रयास है, जो चुनौतियों के बावजूद आत्मनिर्भर बनने की राह पर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति के तहत हर लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के साथ–साथ उनकी समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित किया

प्रधानमंत्री ने 42,000 करोड़ से अधिक की कृषि योजनाओं का किया शुभारंभ, उत्तर प्रदेश के किसानों को मिला सम्मान

लखनऊ, (संवाददाता)। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली से 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें प्रधानमंत्री धान–धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई), दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शामिल हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जे. पी. एस. राठौर वर्चुअली उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने देशभर के 10,000 एफपीओ से जुड़े 50 लाख किसानों को सम्मानित किया, जिनमें से 1,100 "करोड़पति एफपीओ" का वार्षिक कारोबार 1 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के तहत 50,000 से अधिक किसानों का सफल प्रमाणीकरण भी किया गया।उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लखनऊ के 15 किसानों को सम्मानित किया और मिनीकिट

तिलहन, फसल बीमा योजना लाभार्थी किसानों व जैविक खेती करने वाले 5 किसानों को प्रमाणपत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश 2047 तक दाल एवं तेल में आत्मनिर्भर बनने की रणनीति तैयार कर चुका है।प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों को चयनित किया गया है। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, भंडारण और सिंचाई सुविधाओं में सुधार तथा लघु और मध्यम किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है।राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत 75 जनपदों और 318 विकास खंडों में 1,886 क्लस्टरों के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2.35 लाख किसान, 3,772 कृषि सखीध्सीआरपी और 75 बायो रिसोर्स इनपुट सेंटर इस मिशन से जुड़े हैं। मिशन में जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण, डीबीटी प्रोत्साहन, साहित्य किट वितरण और प्राकृतिक प्रमाणीकरण जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत अरहर, उर्द, मसूर, चना, मटर और मूंग की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित कार्ययोजना तैयार की गई है। इस मिशन से किसानों की आय बढ़ेगी, सिंचाई, भंडारण और ऋण सुविधा में सुधार होगा और देश दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा।सहकारिता राज्य मंत्री जे. पी. एस. राठौर ने कहा कि प्रदेश में यूरिया, डीएपी और एमएसपी उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। रबी फसलों के लिए सभी आवश्यक उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। राज्य में 457 नई प्राथमिक कृषि साख समितियों का गठन किया गया है, कुल 1,864 डेयरी सहकारी समितियाँ सक्रिय हैं, 58 मत्स्य सहकारी समितियाँ नई गठित की गई हैं और 1,242 प्रधानमंत्री किसान सेवा केंद्र जुड़ गए हैं।कृषि निदेशक डॉ. पंकज त्रिपाठी ने मंडलीय गोष्ठी में दलहन मिशन एवं धान–धान्य कृषि योजना के सफल क्रियान्वयन का आश्वासन दिया। इस अवसर पर विधायक राम चंद्र यादव, पूर्व विधायक सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी, प्रमुख सचिव कृषि रवींद्र, प्रमुख सचिव सहकारिता सौरभ बाबू, आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता योगेश कुमार, सचिव सिंचाई नवीन कुमार, सचिव कृषि इन्द्र विक्रम सिंह सहित कई अधिकारी और किसान उपस्थित रहे।

पुरानी रंजिश में तीन दोस्तो ने मिलकर एक दोस्त की किया, हत्या शव को बोरे में भरकर नदी में फेका,तीनों गिरफ्तार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर, | मड़ियाहूं तहसील क्षेत्र रामपुर थाना के वाजिदपुर गांव निवासी युवक का शव रविवार को मड़ियाहूं कोतवाली क्षेत्र के मातिवर डिग्री कॉलेज सरौना के पीछे स्थित बसुही नदी में मिलने से सनसनी फैल गई है ।वो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ।इस मामले में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी मड़ियाहूं गिरेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार को लड़के की मां शांति देवी ने थाने पर सूचना दिया कि मेरा पुत्र रामपुर थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गांव निवासी विशाल गौतम (19)वर्ष पुत्र भगेलु गौतम शनिवार की शाम को अपने तीन मित्र लकी गौतम, अजीत गौतम, शुभम गौतम के साथ रामपुर बाजार आया था। देर शाम तक वही तीनों साथी उसके घर पहुंच कर सूचना दिया कि मेला में विशाल गायब हो गया है मिला नहीं। जिसके कारण हम लोग वापस घर चले आए हैं। इसके बाद शांति देवी परिजनों के साथ काफी रात में खोजबीन किया लेकिन बेटे का कुछ पता नहीं चल पाया ।रविवार की सुबह शांति देवी ने रामपुर थाना प्रभारी विनोद कुमार से मिलकर घटना की जानकारी दिया और तीन साथियों का नाम बताया इसके बाद इंस्पेक्टर विनोद कुमार सक्रीय होकर वाजिदपुर गांव पहुंचे और नामजद तीनों युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ किया काफी पूछताछ करने के बाद युवकों ने युवक की हत्या कर बोरा में भरकर मड़ियाहूं कोतवाली क्षेत्र के सरौना गांव स्थित बसुही नदी में फेंकने की जानकारी दिया। पुलिस ने तीनों युवकों के निशानदेही पर बसुही नदी से लाश को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस भिजवा दिया ।घटना के पीछे पुरानी दुश्मनी बताया जा रहा है ।लेकर तीनों युवको ने विशाल को बहला फुसला कर मेला देखने के बहाने ले आए और ले जाकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दिया ।हत्यारों ने विशाल की बांयी कनपटी पर

अंतरराष्ट्रीय मंच पर पूर्वांचल की दो बेटियां चमकीं

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की दो छात्राओं ने बॉयोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट शोध के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय और पूर्वांचल का नाम रोशन किया। लखनऊ स्थित हिन्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आयोजित द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन वेलनेस कॉन द् 2025 में एम.एससी. बॉयोटेक्नोलॉजी की छात्रा आतिफा हफीज को कोविड–19 और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु औषधि खोज पर आधारित उनके शोध एवं प्रभावशाली ऑरल प्रेजेंटेशन के लिए प्रथम पुरस्कार मिला ।वहीं, श्रेया सिंह को कैंसर रिसर्च और सेल डेथ मैकेनिज्म पर आधारित नेक्रोप्टोसिस से कोशकीय मृत्यु में ठब्ड–2 प्रोटीन के प्रभाव पर उनके पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए द्वितीय पुरस्कार दिया गया। यह उपलब्धि विभाग के शिक्षक डॉ. मनीष कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन और 9 पद्मश्री सम्मानित विभूतियों की गरिमामयी उपस्थिति वाले इस प्रतिष्ठित मंच पर हासिल हुई। पूर्वांचल विश्वविद्यालय की यह दोहरी सफलता न केवल शिक्षा और शोध के उच्च मानकों को दर्शाती है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का प्रतीक है। छात्राओं की उपलब्धि पर सोमवार कुलपति डॉ वंदना सिंह सहित अन्य शिक्षकों ने बच्चों को बधाई शुभकामनाएं देते हुए।

संक्षिप्त खबरें

राजकीय आई0टी0आई0 सिद्दीकपुर कैम्पस में रोजगार मेला का आयोजन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । निदेशक, सेवायोजन उ०प्र०, लखनऊ एवं जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जिला सेवायोजन कार्यालय के तत्वाधान में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिद्दीकपुर कैम्पस जौनपुर में 14 अक्टूबर 2025 को प्रातः 10:00 बजे रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। जिसमें निजी क्षेत्र की जे०बी० इंडीस्टीज, सिस्का इलेक्ट्रानिक, एस कंस्ट्रक्शन आदि विभिन्न कम्पनियों में रोजगार हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है, जिसकी शैक्षिक योग्यता:– हाईस्कूल, इण्टर, आई०टी०आई० एवं स्नातक उत्तीर्ण आयुसीमा 18 से 35 वर्ष के अभ्यर्थियों को कैम्पस सलेक्शन करेंगी। जिसमें अभ्यर्थी अपने योग्यतानुसार प्रतिभाग करते हुए, पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से रोजगार प्राप्त करें। जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया की रोजगार मेला में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को अपने साथ समस्त शैक्षिक अभिलेखों की छायाप्रति आई०डी०प्रूफ बायोडाटा सहित प्रतिभाग करेंगे एवं सेवायोजन वेब पोर्टल– https:// rojgaarsangam-up-gov-in के माध्यम से पंजीकरण कर अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करने की अपील की हैं।

लाखों रुपए के अवैध गांजे के साथ एक आरोपी को इनयात नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार

अयोध्या ।थाना इनायत नगर पुलिस ने सोमवार को एक आरोपी को लाखों रुपए की लागत से अवैध गांजा बरामद किया। पुलिस ने उनके पास से कार, फर्जी नंबर प्लेट तथा मोबाइल फोन भी बरामद किया ।इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि सोमवार को थाना इनायतनगर पुलिस एवं एन्टी थेफ्ट टीम पुलिस ने चेकिंग के दौरान को अवैध गांजा का व्यापार करने वाले व्यापारी सोनू कुमार पासवान पुत्र बाबूलाल उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम पूरे बंजरिया , शाहबाबाद ग्रन्ट थाना इनायतनगर जनपद अयोध्या को 91 किलो अवैध गांजा अनुमानित कीमत करीब 22 लाख रुपये व वाहन मे प्रयुक्त होण्डा सिटी कार के साथ ग्राम नगरहन का पुरवा स्थित पुलिया के पास से बजे गिरफ्तार किया। इस संबंध में एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया पकड़ा गया आरोपी सिर्फ अवैध गज का भंडारण करके आसपास बेचने का कारोबार करता था पहले आरोपी पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर में यह अवैध कारोबार करता था लेकिन वहां की पुलिस की सक्रियता के चलते उसने यहां पर अपना जाल फैलाया। बताया कि यह सफलता सीओ मिल्कीपुर श्रेयश त्रिपाठी की देखरेख में थानाध्यक्ष इनायत नगर रतन शर्मा व एन्टी थेफ्ट टीम के अलावा उ0नि0 अमर बहादुर पटेल, थाना इनायत नगर को पुलिस कर्मियों को मिली।

डीएम ऑफिस के सामने सामाजिक कार्यकर्ता ने ज्वलनसील पदार्थ डालकर आत्महत्या का किया प्रयास

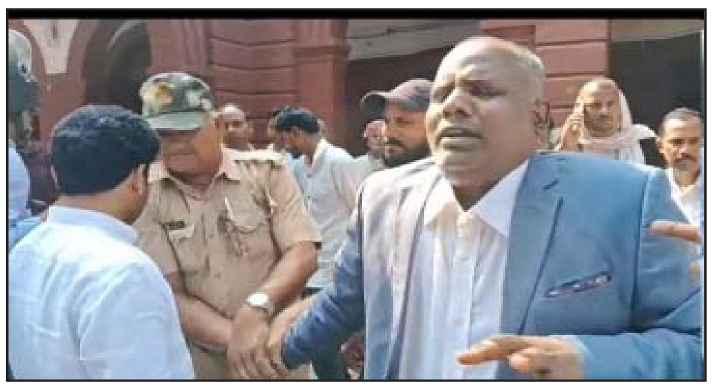

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम कार्यालय के सामने सोमवार की दोपहर करीब ढाई बजे एक अधेड़ अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया ।मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे बचा लिया। जानकारी के अनुसार खेतासराय थाना क्षेत्र के रुधौली गांव निवासी जंगबहादुर गौतम सोमवार को ज्वलनशील पदार्थ लेकर डीएम ऑफिस पहुंचा। और वहां परिसर में ही अपनी बातों को कहते हुए अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालने लगा। इसे देख आनन फानन में चार पांच पुलिसकर्मी उसकी तरफ दौड़े। और उसको आत्मदाह करने से बचाया। और इसकी सूचना तुरन्त स्थानीय पुलिस व अधिकारियों को दी। मौके पर पहुंची लाइन बाजार पुलिस जंगबहादुर को थाने ले गयी। और मामले की जानकारी में जुट गई है। हालांकि एलआईयू टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस के पकड़ने के बाद जंगबहादुर गौतम ने कहा कि यहां के अस्पतालों में भ्रूण हत्या कराई जाती है ।इसमें यहां पर उन्होंने सीएमओ की भी सलंपिता का भी आरोप लगाया है। उसका कहना है कि इसकी शिकायत मेरे द्वारा सीएम पोर्टल से लेकर स्थानीय प्रसाशन को दिया ।लेकिन अबतक कोई सुनवाई नही हुई। मेरे शिकायती प्रार्थना पत्र देने के बाद मुझे जान से मारने की धमकी आने लगी। इससे तंग आकर मैं अपनी जान देना चाहता हूं। वही इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह ने बताया कि अभी मामले की जानकारी मिली है। उसके अनुसार जंगबहादुर गौतम पुत्र मिठाई लाल गांव रुधौली थाना खेतासराय के रहने वाले है। इनका कहना है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और जो भी सामाजिक समस्याएं है उसको लेकर मैं सामाजिक रूप से काम करता हूँ।

नगर पालिका कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया ज्ञापन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। नगर पालिका कर्मचारी संघ ने नगर पालिका परिषद, के समस्त कर्मचारियों ने अपनी प्रमुख 8 मांगों को लेकर अधिशासी अधिकारी से सोमवार को मुलाकात किया। संघ ने मांगों के तत्काल निदान की अपील की है, जिनमें संविदा कर्मियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ, कर्मचारियों के मासिक वेतन का भुगतान और संगठन भवन की व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। संघ की प्रमुख मांगों में से एक यह है कि नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर की तर्ज पर जौनपुर के संविदा कर्मियो को नवंबर में सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए। इसके अतिरिक्त, राज्य वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम समस्त कर्मचारियों के मासिक वेतन और बकाया भुगतान के लिए किया जाए, उसके बाद ही अन्य मदों में खर्च किया जाए। कर्मचारियों को पूर्व की भांति जाड़े की वर्दी उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है। संघ ने स्थायी कर्मचारियों की सर्विस बुक में नॉमिनी दर्ज करने का रुका हुआ कार्य अविलंब पूरा कराने का आग्रह किया है। साथ ही, सभी पालिका कर्मियों को ए.सी.पी. (एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन) का लाभ दिलाने की भी मांग की गई है, जो बार–बार कहने पर भी नहीं मिल रहा है। आउटसोर्सिंग कर्मियों के पी.एफ. (भविष्य निधि) के संबंध में भी गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई हैं। संघ का कहना है कि उनके खातों में पी.एफ. का पैसा अनियमित और कम–ज्यादा करके भेजा जाता है, और हर माह जमा नहीं होता। इसे नियमित रूप से उचित धनराशि के साथ समय पर जमा कराया जाए और उसका हिसाब संघ को उपलब्ध कराया जाए। मृतक या नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों के पी.एफ. की जमा धनराशि उनके परिवार वालों को दिलाने की भी मांग की गई है। ठेकेदार द्वारा आउटसोर्स कर्मियों को अभी तक हेल्थ कार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिन्हें तत्काल दिलाया जाए। नगर पालिका कर्मचारी संगठन के भवन की मांग काफी समय से लंबित है। इस पर अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति भी दी जा चुकी है और यह समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद, संगठन को अभी तक भवन की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण संगठन के पदाधिकारी और कर्मचारी धूप में या पेड़ के नीचे बैठने को मजबूर हैं। संघ ने इस समस्या का शीघ्र निदान करने की मांग की है।

संक्षिप्त खबरें

दीपावली पर्व पर 17 से 1 नवंबर के बीच यात्रियों की संख्या पर होगी रोडवेज बसों की फेरो मे बढोत्तरी

अयोध्या। दीपावली सहित अन्य पर्वो को देखते हुए रोडवेज बसों के फेरों के साथ साथ उनकी संख्या में बढ़ोतरी होंगी ।इस संबंध में सहायक प्रबंधक रोडवेज अयोध्या डिपो आदित्य प्रकाश ने बताया कि बस यात्रियों को यह सुविधा 17 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच तक मिलेगी ।जो प्रयागराज, लखनऊ,अम्बेडकर नगर, रायबरेली सहित कई मार्गो पर संचालित होंगी ।उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में धनतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली पर्व, भैया दूज छठ पूजा पर्व पडेगे ।जिसके चलते दूर दूराज से बाहर से आने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है ।इसलिए बस यात्रियों के सुविधा के लिए बसों की संख्या भी बढ़ानी पर रही है। बताया कि इस समय अयोध्या डिपो से कुल 147 बसों का संचालन विभिन्न रूटों पर हैं जिनमें से 121 रोडवेज निगम की बसे हैं, और 26 बसें अनुबंधित हैं ।इन बसों के फेरों मे बढ़ोतरी आने वाले दिनों मे यात्रियों की संख्या के अनुसार बढ़ाई जाएगी ।बताया कि इसके अलावा 70 बसें अमेठी, सुल्तानपुर तथा अंबेडकर नगर जिलों से भी मंगाई जाएगी ।जो यात्रियों के संख्या के मुताबिक विभिन्न मार्गों पर संचालित होगी।

साकेत महाविद्यालय मे हुआ शक्ति स्वरूपा विश्व हिंदू परिषद कार्यक्रम का आयोजन

अयोध्या। शनिवार को साकेत महाविद्यालय मे शक्ति स्वरूपा विश्व हिंदू परिषद अयोध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य महिला आयोग सदस्य अपर्णा यादव ,डॉक्टर मंजूषा पांडे के अलावा महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला मौजूद रही। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आई महिला आयोग की सदस्य शहर पड़ा यादव ने कहा कि महिलाएं आज समाज के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। राजनीतिक क्षेत्र हो शिक्षा का क्षेत्र हो विज्ञान का क्षेत्र हो खेल का क्षेत्र हो का क्षेत्र हो हर क्षेत्र में महिलाएं अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वहां पर मौजूद महिला थाना अध्यक्ष आशा शुक्ला ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें मिशन शक्ति पेज 5 भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इस समय शासन द्वारा एक से बढ़कर एक कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है जिसका लाभ महिलाओं व बालिकाओं को मिल रहा है ।कहा कि शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या योजना और हेल्पलाइन नंबर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया। उन्होंने महिला अपराध संबंधित अपराध के बारे में अवगत कराया गया ।उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के बारे में बताया गया ।इस मौके पर उनके अलावा उप निरीक्षक प्रिया, महिला आरक्षी नेहा मिश्रा व महिला आरक्षी पूनम यादव द्वारा

बदलापुर महोत्सव 1, 2, 3 नवम्बर को प्रस्तावित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र की अध्यक्षता और मा0 विधायक बदलापुर श्री रमेश चंद्र मिश्र की गरिमामयी उपस्थिति में सल्तनत बहादुर इंटर कॉलेज में बदलापुर महोत्सव मनाए जाने के संबंध में इंदिरा गाधी स्टेडियम सिद्दीकपुर में बैठक संपन्न हुई। बैठक में विधायक ने बताया कि दिनांक 01, 02 और 03 नवम्बर 2025 को बदलापुर महोत्सव मनाया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यान विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, जिला पंचायत राज विभाग सहित अन्य विभागों के द्वारा स्टाल लगाकर विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पात्रों को रजिस्ट्रेशन कराया जाना भी सुनिश्चित करें। विधायक के द्वारा निर्देश दिया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा स्वास्थ्य कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच और आवश्यक दवाई उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि सामूहिक विवाह योजना के संबंध में समस्त जोड़ों की शादियां कराए जाने के सम्बन्ध में शत–प्रतिशत सत्यापन कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में लापरवाही बर्दास्त नही की जायेगी। उन्होंने कहा कि सीएम युवा उद्यमी विकास योजना में अधिक से अधिक आवेदन कराया जाये, जिससे अधिक से अधिक पात्र व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को महोत्सव के दौरान साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। महोत्सव में 01 नवम्बर को सामूहिक विवाह का आयोजन किया जायेगा। 02 और 03 नवम्बर 2025 को विभागों के द्वारा स्टॉल लगाया जायेगा, जिसमें शासन की योजनाओं का प्रचार–प्रसार कराया जायेगा साथ ही विधायक खेल स्पर्धा का भी आयोजन किया जायेगा, जिसमें विजेताओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। साथ ही विधायक ने कहा कि महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जाना है जिसके लिए स्थानीय और बाह्य कलाकारों को भी मंच उपलब्ध कराया जाये। पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया कि ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। महिला पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई जाए। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी परियोजना निदेशक रहेंगे। जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र द्वारा समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी अधिकारी अपने अपने दायित्वों का शत–प्रतिशत निर्वहन करते हुए महोत्सव को सफल बनाये। इस अवसर पर समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

रसोईघर के अपशिष्ट से बन सकेगी ऊर्जा: प्रो. ओपी. सिन्हा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के सेंटर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एवं प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) भौतिक विज्ञान अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में "एडवांस्ड फंक्शनल मैटेरियल्स फॉर एनर्जी एप्लिकेशंस" विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन सोमवार को किया गया। यह सेमिनार विश्वविद्यालय को प्राप्त भारत सरकार के डीएसटीदृपर्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत आयोजित किया गया। इस अवसर पर वक्ता के रूप में प्रो. ओपी सिन्हा, निदेशक, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ नैनोटेक्नोलॉजी, एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा ने अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा के संचयन की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि रसोईघर से उत्पन्न सब्जियों और अन्य जैविक अपशिष्टों से ऊर्जा संचयन हेतु उच्च दक्षता वाले सुपरकैपेसिटर उपकरण विकसित किए जा सकते हैं। अध्यक्षीय संबोधन में कुलपति प्रो. वंदना सिंह कहा कि भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च दक्षता वाले फंक्शनल मटेरियल्स के विकास की आवश्यकता है। इन पदार्थों के माध्यम से देश में ऊर्जा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ेगा। एम.एन.एन.आई.टी. प्रयागराज से प्रो. एस. एन. पांडेय ने सुपरकैपेसिटर और बैटरियों के लिए उपयोगी उन्नत पदार्थों के गुणधर्मों पर चर्चा की। वहीं डॉ. उपेन्द्र कुमार ने फ्यूल सेल निर्माण और हाइड्रोजन ऊर्जा के विकास में फंक्शनल पदार्थों की भूमिका पर विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत किया। आई.आई.टी. इंदौर से प्रो. मृगेन्द्र दुबे सॉफ्ट पदार्थों के ऊर्जा क्षेत्र में अनुप्रयोगों पर विस्तार से चर्चा की ।विभिन्न तकनीकी सत्रों में आमंत्रित विशेषज्ञों ने अपने शोध अनुभव साझा किए। रज्जू भैया संस्थान के निदेशक प्रो. प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में फंक्शनल एवं नैनोस्ट्रक्चर्ड पदार्थों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन ईंधन, उच्च क्षमता वाली बैटरियों और ऊर्जा भंडारण तकनीकों के विकास में ये पदार्थ नवाचार का आधार बन रहे हैं। विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रो. राजेश शर्मा ने कहा कि ऊर्जा दोहन के क्षेत्र में हमें सूक्ष्मजीवी प्रणालियों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्ति पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वहीं अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ के समन्वयक प्रो. देवराज सिंह ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में सौर ऊर्जा के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम के संयोजक डॉ. धीरेंद्र कुमार चौधरी ने सेमिनार की रूपरेखा प्रस्तुत की। संचालन डॉ. काजल कुमार डे और डॉ. सुजीत के. चौरसिया ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ ने दिया धरना पांच सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ जनपद शाखा जौनपुर के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है। यह ज्ञापन जिलाधिकारी जौनपुर के माध्यम से भेजा गया, जिसमें निजीकरण रोकने, पुरानी पेंशन बहाल करने, मृतक आश्रितों को योग्यतानुसार नौकरी देने और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती खोलने सहित पांच सूत्रीय मांगें रखी गई हैं। महासंघ के जिलाध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने कहा कि निजीकरण के कारण आंगनवाड़ी, आशा, शिक्षामित्र, रोजगार सेवक, पंचायत कर्मी, रसोइया और आंगनवाड़ी सहायिका सहित अन्य विभागों में कार्यरत लोगों के परिवारों का भरण–पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम लाल गौतम, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और जिला मंत्री सभाजीत यादव ने मांग की कि चतुर्थ श्रेणी के मृतक आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार समूह श्गश के पद पर नियुक्ति दी जाए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष केसरी प्रसाद गौतम और कोषाध्यक्ष अजय लाल मौर्या ने मुख्यमंत्री से चतुर्थ श्रेणी की भर्ती खोलने और निजीकरण को पूरी तरह बंद करने का आग्रह किया। चतुर्थ श्रेणी के संरक्षक सरताज सिंह ने पुरानी पेंशन को कर्मचारियों और शिक्षकों के बुढ़ापे का सहारा बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह माननीय सांसदों और विधायकों को पुरानी पेंशन मिल रही है, उसी तरह अर्धसैनिक बलों, कर्मचारियों और शिक्षकों को भी यह सुविधा मिलनी चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 9 नवंबर 2025 को प्रदेश के कर्मचारी और शिक्षक डॉ. मंजीत सिंह पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में दिल्ली कूच करेंगे। इस ज्ञापन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष अनर बहादुर यादव, जिला मंत्री तेज बहादुर, विपिन कुमार यादव, प्रमोद अग्रहरि, कुलदीप यादव, मुफ्तीगंज ब्लॉक अध्यक्ष सी.पी. सिंह, सिरकोनी ब्लॉक अध्यक्ष अनामिका सिंह, अशोक कुमार, प्रदीप कुमार, बबलू श्रीवास्तव, लवकुश यादव, रेखा देवी, मधुबाला, आशा पाल, मनोज कुमार, नन्हकू यादव, राम हृदय और प्रमोद कुमार शर्मा सहित ।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 – 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com
समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।